VNK-BHS/2A/3.00

श्री विजय गोयल : सर, मॉर्निंग में सबके साथ यह तय हुआ था।...(व्यवधान)... यह पहले से लगा हुआ है।...(व्यवधान)...

श्री नरेश अग्रवाल : नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : नरेश जी, कृपया आप बैठिए।...(व्यवधान)... Naresh*ji,* I will explain the position. Please bear with me. Actually, the Statutory Resolution is included in the List of Business before Short Duration Discussion. It is already there. ...(Interruptions)... No; let me say. Otherwise, I should have earlier announced and taken an exemption or approval. It is already there. So, it is a matter of two minutes only. ...(Interruptions)... Two minutes only. ...(Interruptions)...

श्री नरेश अग्रवाल : सर, यह परंपरा की बात है, दो मिनट की बात नहीं है। हरदम परंपरा रही है कि Short Duration Discussion हो, तो वह दो बजे के बाद सबसे पहले शुरू हो। संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी ने कहा कि 31 तारीख तक दिल्ली वाला बिल पास होना जरूरी है।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : मैंने भी बोला था।...(व्यवधान)...

श्री नरेश अग्रवाल : अगर यह आज पास नहीं हुआ, तो यह कैसे जाएगा? हम लोगों ने कहा कि ठीक है, पहले इसको पास कर लीजिए।...(व्यवधान)...

श्री विजय गोयल : मैं नरेश जी से सहमत हूँ।...(व्यवधान)...

श्री नरेश अग्रवाल : सर, मंत्री लोगों को बैठे भी रहने दीजिए। मंत्री जी इसको पेश करेंगे और अभी अपने घर चले जाएंगे।...(व्यवधान)... इन्हें शाम तक बैठे रहने दीजिए।...(व्यवधान)...

श्री विजय गोयल : नरेश जी, ये नहीं जाएंगे।...(व्यवधान)... नरेश जी, कृपया आप मेरी बात तो सुनिए।...(व्यवधान)...

श्री नरेश अग्रवाल : ऐसे नहीं हो पाएगा।...(व्यवधान)... मंत्री जी तफरीह करने आ रहे हैं।...(व्यवधान)... ये लोग मंत्री बने हैं, तो रात-रात तक यहां बैठें।...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes. ...(Interruptions)... I agree. ...(Interruptions)...

श्री विजय गोयल : नरेश जी, मैं आपसे सहमत हूँ कि परंपरा यही है कि दो बजे सबसे पहले Short Duration Discussion होगा, पर चेयरमैन साहब ने आपसे आज कहा था कि exception के रूप में आज इसको मान लीजिए।...(व्यवधान)...

श्री नरेश अग्रवाल : नहीं, इस पर बिल्कुल नहीं कहा था।...(व्यवधान)... यह कतई नहीं कहा था।...(व्यवधान)...

श्री विजय गोयल : यह दो-दो मिनट का है, इसलिए इसको होने दीजिए।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : नरेश जी, आपने जो बोला, वह ठीक है, मैं भी आपसे सहमत हूँ।...(व्यवधान)... I agree with you. But the position now, unfortunately, is that I have already called and the Minister has already moved. ...(Interruptions)... The Minister has already moved. ...(Interruptions)...

श्री नरेश अग्रवाल : सर, यह गलत है।...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What do we do? ...(Interruptions)...

श्री नरेश अग्रवाल : सर, Statutory Resolution पर हम लोग बोलेंगे।...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No name is given. ...(Interruptions)...

श्री नरेश अग्रवाल : तो क्या हुआ, हम बोलेंगे।...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. ...(Interruptions)... ऐसा नहीं हो सकता है, आपने नाम नहीं दिया है।...(व्यवधान)...

श्री नरेश अग्रवाल : Statutory Motion ऐसे पास नहीं हो जाएगा।...(व्यवधान)... किस पर कितनी ड्यूटी बढ़ी है, किस पर क्या है, हम उस पर बोलेंगे।...(व्यवधान).. हम इसको ऐसे थोड़े ही छोड़ देंगे।...(व्यवधान)... अभी हम इसके बाद आपके पास स्लिप भेजेंगे।...(व्यवधान)... पहले Short Duration Discussion होगा। उसके बाद यह होगा।...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. ...(Interruptions)... List of Business में ऐसा नहीं है।...(व्यवधान)...

श्री नरेश अग्रवाल : सर, यह तय नहीं हुआ था।...(व्यवधान)... यह बिल्कुल तय नहीं हुआ था।...(व्यवधान)... जो तय हुआ, हम उसको मान रहे हैं।...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What you want is that there should be two-and-a-half hours for Short Duration Discussion. ...(Interruptions)... This, we can dispose of in five minutes. ...(Interruptions)...

श्री नरेश अग्रवाल : सर, हम रात के आठ बजे तक बैठने के लिए तैयार हैं।...(व्यवधान)... आज चेयरमैन साहब ने कहा है कि चाहे कोई बिल हो, चाहे कोई Resolution हो, वह बिना डिस्कशन के पास नहीं होगा।...(व्यवधान)... आज सवेरे ही चेयरमैन साहब ने कहा है।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : हां, उन्होंने ऐसा बोला है। मैं भी इससे सहमत हूँ।...(व्यवधान)...

श्री नरेश अग्रवाल : अगर उन्होंने ऐसा बोला है, तो यह कैसे दो मिनट में पास हो जाएगा?...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : ऐसा इसलिए संभव है, क्योंकि इस पर कोई नाम नहीं आया है।...(व्यवधान)...

श्री नरेश अग्रवाल : सर, चूंकि यह बाद में होना है, इसलिए अभी इस पर नाम नहीं आया है।...(व्यवधान)... इस पर नाम आएगा।...(व्यवधान)...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir,.....(Interruptions)...

श्री विजय गोयल : सर, क्या एक अकेले नरेश अग्रवाल हाउस को चलाएंगे?...(व्यवधान)... क्या नरेश अग्रवाल हाउस चलाएंगे?...(व्यवधान)... यह बहुत ज्यादती है।...(व्यवधान)... सवेरे तय कुछ हुआ है और आप कुछ और कीजिए।...(व्यवधान)... आप क्या यह समझते हैं कि बिजनेस सिर्फ गवर्नमेंट का काम है, ऐसा नहीं है, बल्कि यह देश का काम है।...(व्यवधान)... यह सिर्फ सरकार का काम नहीं है, बल्कि हम यह देश का काम कर रहे हैं।...(व्यवधान)...

श्री नरेश अग्रवाल : हम लोगों ने कल दो बिल पास करा दिए।...(व्यवधान)...

श्री विजय गोयल : आप चेयरमैन साहब की बात तो मानिए।...(व्यवधान)...

श्री नरेश अग्रवाल : मैंने पहले यह कहा था कि ठीक है, इस बिल को पहले पास करा लीजिए, लेकिन यह Short Duration Discussion के बाद होगा।...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: My problem is, it is in the List of Business before the Short Duration Discussion. ...(Interruptions)...

श्री विजय गोयल : एक बिल तो रखा जा चुका है, उसको तो कीजिए।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आप लोग अभी बैठिए। I will explain. ...(Interruptions)...

SHRI DEREK O'BRIEN: No, no, Sir. ...(Interruptions)... Before you took up the NCT Bill at four minutes past 2 o' clock, Sir, with due respect you made a statement that after we pass this, we are going to take up the Short Duration Discussion. ...(Interruptions)... Where is the problem? ...(Interruptions)... We will sit down and pass it for them at 5.30 p.m. ...(Interruptions)... But you yourself said, Sir, with due respect to you.....(Interruptions)... You said that. ...(Interruptions)... You check the record. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You are correct. ...(Interruptions)... I said that. ...(Interruptions)... No, no. ...(Interruptions)... Naresh*ji*. ...(Interruptions)... Naresh*ji*, yes, I said that. At that point of time, it did not come to my mind that Statutory Resolution is listed before Short Duration Discussion. It did not come to my mind. ...(Interruptions)... That is the point.

श्री नरेश अग्रवाल : माननीय उपसभापति जी, सवेरे सबके माइंड में था, हम लोगों ने पूरा एजेंडा देखा था और चेयरमैन साहब ने कहा था कि इसको पास करा दीजिए, फिर ढाई बजे से Short Duration Discussion के लिए कहा था।....(व्यवधान)...

(2बी/एनकेआर-आरएसएस पर जारी)

NKR-RSS/2B/3.05

श्री नरेश अग्रवाल (क्रमागत) : हमसे Short Duration Discussion 2.30 बजे लेने के लिए कहा गया था, अब 3.05 हो गए हैं। ..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : लेकिन ऐसा क्यों हो गया? ..(व्यवधान)..

श्री नरेश अग्रवाल : हमने कहा कि अगर पास कराना है तो चलिए हो जाने दीजिए।..(व्यवधान).. लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि बिल लिया जाएगा।.(व्यवधान)..

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : अगर आपकी इतनी ज़िद है, तो इसके बाद आप नाबार्ड से संबंधित बिल भी पास करा दें।..(व्यवधान)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN : All right. मंत्री जी, बैठिए। No,no. ..(व्यवधान).. आप सुनिए। Okay. Now, listen. We will take up Short Duration Discussion first. Time allotted for Short Duration Discussion is two hours thirty minutes because time is restricted to that. After that, we will take up the Statutory Resolutions. Okay. Agreed. Now, Short Duration Discussion.

SHRI NEERAJ SHEKHAR: Sir, after that, will we take up the NBARD Bill? ..(व्यवधान)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Now, I will take up the Short Duration Discussion first, and after that, we will take up Statutory Resolutions.

SHORT DURATION DISCUSSION ON EXCESSIVELY HIGH LEVELS OF AIR POLLUTION IN DELHI

श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, बहुत दिनों के बाद आज Short Duration Discussion पर हमें कुछ कहने का मौका मिल रहा है, लेकिन जो सदन की एक परम्परा थी, माननीय उपसभापति जी एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, वह परम्परा थी कि हर सप्ताह में एक Calling Attention और दो Short Duration Discussions लिए जाएंगे, वह परम्परा टूट रही है,..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : इसे आप सुबह चेयरमैन साहब के सामने discussion के समय बोलिए।

श्री नरेश अग्रवाल : हम बोलते हैं, लेकिन आप चुप रहते हैं। यही मुश्किल है। हमने बोला लेकिन आप चुप हो गए।..(व्यवधान).. आप भी बोलिए। जो एक परम्परा थी, वह परम्परा कम-से-कम कायम रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत important issues हमारे सामने हैं। हम चाहते हैं कि देश से जुड़े issues का कुछ समाधान निकले। हमारा काम खाली यहां आलोचना करना नहीं है, हम सुझाव भी देंगे।

श्री उपसभापति : यहां सरकारी Business भी चलना है और discussion भी होना है। दोनों काम करने हैं, ..(व्यवधान).. by cooperation. We should cooperate.

श्री विजय गोयल : नरेश जी, आपकी breaking news बहुत आती हैं। ..(व्यवधान)..

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, how much time has been allotted for the Short Duration Discussion?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Two hours thirty minutes.

SHRI JAIRAM RAMESH: And how much time will the Minister take to give his reply? Will he take two-and-a-half hours?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Minister's reply will be in less than thirty minutes. The Minister will not be given more than thirty minutes.

श्री नरेश अग्रवाल : माननीय उपसभापति जी, आज पर्यावरण की जो हालत है, उसे लेकर पूरा विश्व चिंतित हैं। ऐसा नहीं कि खाली हिन्दुस्तान ही चिंतित है, पूरा विश्व चिंतित है। अगर हर फिगर में हम सबसे टॉप पर आते हैं, तो हमें और ज्यादा चिंता होनी चाहिए। दिसम्बर का महीना है। आप देख लीजिए कि ठंड पड़ रही है। जब सुबह मैं टहलने जा रहा था तो मेरा Security वाला बोला कि साहब, आप मत टहलिए। कोहरा है, पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा है। इस पॉल्यूशन में टहलने से ज्यादा नुकसान होगा। अगर राजधानी में, जहां देश की सरकार रहती है, जिसे सारे लेन-देन करने हैं, अगर राजधानी की स्थिति ऐसी रहेगी तो विश्व में हमारी क्या image बनेगी? श्रीलंका की क्रिकेट टीम जब यहां खेलने आई, दिल्ली में क्रिकेट मैच था, उनके प्लेयर्स मास्क लगाकर खेले, जिन्हें पूरे विश्व में टेलीविज़न पर देखा गया, क्या वह हमारे देश के लिए बहुत अच्छा रहा? अमेरिका ने दिल्ली आने वाली अपनी Airlines कैंसिल कर दीं तथा

यूरोप और अमेरिका में advisory जारी की गई कि दिल्ली की पॉल्यूशन की स्थिति बहुत खराब है, आप भारतवर्ष मत जाइए - क्या वह हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ?

आज विश्व के जो पाँच सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं, उनमें एक नम्बर पर दिल्ली, दूसरे नम्बर पर बीज़िंग, तीसरे नम्बर पर सीटल, चौथे नम्बर पर एक्सपोसिटी और पांचवें नम्बर पर कायरो है। ..(व्यवधान).. नहीं, पाकिस्तान का कोई सिटी नहीं है। जो पाँच विश्व के सबसे पॉल्यूटेड शहर हैं, उनमें दिल्ली का नाम है। पर्यावरण मंत्री जी, आप भी दिल्ली के रहने वाले हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी, आप भी दिल्ली के रहने वाले हैं। हमें देखना होगा कि स्थिति बिगड़ क्यों रही है? इस पर हम लोगों ने अब तक क्या किया? हर साल जब सर्दी आती है, पॉल्यूशन की स्थिति खराब होती है लेकिन दोष किसानों पर मढ़ दिया जाता है।

(2सी/DS द्वारा जारी)

DS-KGG/3.10/2C

श्री नरेश अग्रवाल (क्रमागत) : कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसान जो पराली जलाते हैं, उसके कारण दिल्ली में प्रदूषण है, लेकिन क्या यह सही स्थिति है? वे तो सैकड़ों सालों से जलाते चले आ रहे हैं। क्या सैकड़ों साल पहले दिल्ली कभी इतनी पॉल्यूटेड हुई? पिछले तीन-चार साल से दिल्ली इतनी पॉल्यूटेड क्यों होने लगी? क्या ऐसा किसानों की वजह से हुआ? सरकार ने तमाम घोषणाएँ कीं। हरियाणा सरकार ने कहा कि हम पराली का compensation देंगे। सब लोग कहते तो हैं, लेकिन होता क्या है? मैं आज अख़बार में पढ़ रहा था कि पर्यावरण मंत्रालय ने यह कहा है कि हम 12-सूत्री कार्यक्रम बना रहे हैं। जब मैंने अख़बार में उस 12-सूत्री कार्यक्रम को पढ़ा,

तो मुझे हँसी आ गई। उसमें लिखा था- "मैं राज्य सरकार को यह निर्देश दूँगा, मैं फॉरेस्ट विभाग को यह निर्देश दूँगा।" केवल निर्देश देने से अगर पॉल्यूशन खत्म हो जाए, तो फिर निर्देश देने में कितना समय लगता है? हमें आप दे दो, हम यहीं पर से वे निर्देश पढ़ दें। शायद वह अख़बार में न छप पाए, लेकिन यहाँ तो पूरा विश्व देख रहा है, सभी लोग टीवी देख रहे हैं। अगर आप केन्द्र की सरकार से पूछिए, तो सुनने को मिलता है कि दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर रही है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति बीजिंग की यात्रा पर जा रहे थे, तो चाइना की सरकार ने पॉल्यूशन की खराब स्थिति के लिए वहाँ पर आर्टिफिशियल पानी गिराया और अमेरिका के राष्ट्रपति वहाँ तब गए, जब वहाँ पॉल्यूशन खत्म हो गया।

हमने एनजीटी बना दिया। यह सोचा गया था कि एनजीटी बन जाएगा, तो सारा पर्यावरण एकदम ठीक हो जाएगा। वे जज रिटायर हो गए। उन पर खुद ही आरोप लग गए थे। किसने लगाए, यह मैं नहीं बोलूँगा। श्रीमन्, उन्होंने तुगलकी फरमान जारी करने शुरू कर दिए। उनके फरमान के बाद अगर किसान अपने खेत से एक छटांक भी मिट्टी लेना चाहे, जिससे उसे अपने घर की लिपाई करनी है, क्योंकि गाँव में कच्चे मकान हैं, तो वह मिट्टी नहीं खोद सकता, पुलिस वाला उसको बन्द कर देगा। कोई आदमी अपने आप उन पेड़ों को भी नहीं काट सकता, जो प्रतिबंधित नहीं हैं। एनजीटी ने दिल्ली में पॉल्यूशन ठीक करने का टैक्स लगाया। उसका करीब 800 करोड़ रुपया आपके पास जमा है, वह रुपया क्या कर रहा है? पर्यावरण मंत्रालय कहता है कि वह दिल्ली सरकार के अधीन है, उसको दिल्ली सरकार देखेगी और दिल्ली सरकार कहती है कि हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, सब अधिकार भारत सरकार के पास हैं। ये सब

दोनों की लड़ाई के बीच में पड़ा हुआ है। अगर हम इन चीज़ों पर नहीं जाएँगे और सत्यता पर नहीं जाएँगे, तो पॉल्यूशन की बिगड़ती स्थिति लोगों को लंग्स का रोगी बना रही है, हृदय का रोगी बना रही है, साँस का रोगी बना रही है, कैंसर का रोगी बना रही है और आँखें भी खराब कर रही है। जब हम अपनी आँख डा. टिटियाल को दिखाने गए, तो उन्होंने कहा कि पॉल्यूशन के कारण ऐसा है। हमारे पुराने संसदीय कार्य मंत्री अब कैबिनेट मिनिस्टर हो गए हैं, पहले ये हमारी आँखें दिखवा देते थे, लेकिन अब ये चले गए, तो हमें खुद ही दिखानी पड़ रही हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Not only eyes, but also the chest.

श्री नरेश अग्रवाल : उसके कारण चेस्ट प्रॉब्लम भी होती है और आइज़ प्रॉब्लम भी होती है। वे कहने लगे कि यह पॉल्यूशन की वजह से है। यह बताइए कि आम लोगों की क्या हालत है? दिल्ली में जिन-जिन जगहों पर आपके इंटर-स्टेट बस स्टैंड हैं, वे सारी जगहें, जहाँ इंटर-स्टेट बसें आकर खड़ी होती हैं, वहाँ की क्या हालत है? मैं नाम लिखकर नहीं लाया हूँ, लेकिन दिल्ली में ऐसी तमाम जगहें हैं, जहाँ पर बस अड्डे हैं, वहाँ पर प्रदूषण की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। वह पराली के कारण खराब नहीं है, बल्कि बसों के कारण है। आज यहाँ कितने व्हिकल्स निकल रहे हैं? हमें यही नहीं मालूम कि दिल्ली में या इंडिया में कितने व्हिकल्स प्रतिदिन निकल रहे हैं। उन पर रोक लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या आपको मालूम है कि सिंगापुर में आप दूसरी गाड़ी तब तक नहीं खरीद सकते, जब तक सरकार की परमिशन न मिल जाए? आपने ऑड-ईवन व्यवस्था चला दी और उस ऑड-ईवन के कारण लोगों ने यह सोचकर और एक्स्ट्रा गाड़ियाँ खरीद लीं कि एक ऑड नम्बर की गाड़ी रख लो और एक ईवन नम्बर

की गाड़ी रख लो। इसका यह कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमको यह सब देखना पड़ेगा। अगर हमने नहीं देखा, तो केवल यह न हो जाए कि सदन में इस पर चर्चा हुई थी। अगर चर्चा के अलावा सत्यता रहेगी, तो ज्यादा अच्छा है।

(2डी/एमसीएम पर जारी)

MCM-SSS/2D/3.15

श्री नरेश अग्रवाल (क्रमागत) : अब तो यह होता है कि राजस्थान में बाढ़ आ गई। एकदम हम लोगों को हंसी आती है कि राजस्थान के उन इलाकों में जहां दस साल से पानी नहीं गिरता था, जहां लोग पानी नहीं देखते थे, दुबई तक तो पानी गिरने लगा। हमारे यहां बुंदेलखंड जहां सूखा ही सूखा पड़ता था, वहां अच्छा पानी गिरने लगा। यह पर्यावरण का चेंज नहीं है तो क्या है? वन लगाने की बात है, सब जानते हैं कि पेड़ की कटाई से पर्यावरण की स्थिति बहुत खराब हुई है।

(उपसभाध्यक्ष, श्री भुवनेश्वर कालिता पीठासीन हुए)

सब वैज्ञानिक इस बात को कहते भी हैं। यह हुआ कि जितनी लैंड है, उसका 33 परसेंट फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए। World wild life fund ने उत्तर प्रदेश में तीन बार इतने पेड़ लगा दिए कि उत्तर प्रदेश में कहीं जमीन बची ही नहीं। वर्ल्ड बैंक से जब लोन लिया तो तीन बार इतने पेड़ लगा दिए कि हर तीन फीट पर एक पेड़ लग गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में 12 परसेंट से ऊपर वन नहीं है। उत्तरांचल हटने के बाद तो और बुरी हालत हो गई। तो क्या हमने पॉलिसी बनाई कि फॉरेस्ट एरिया कैसे बढ़ाएं? मैं तो कहता हूं कि अभी भी तमाम नंगे पहाड़ खड़े हुए हैं। आप बद्रीनाथ साइड चले जाइए, एक पेड़ आपको नहीं मिलेगा, केदारनाथ की कुछ ऊंचाई पर जाइए वहां भी नहीं है,

गंगोत्री में तो आपको पेड़ ही नहीं मिलेगा। उन पहाड़ों के लिए जब हमारे से जर्मन और फ्रांस के एक्सपर्ट कहते हैं कि आप हमको दे दीजिए, हम वहां पेड़ लगा देंगे, आपके पहाड़ पूरे हरे कर देंगे, तो क्या दिक्कत है आपको? अब जब डब्लू0टी0ओ0 लागू हो गया, एफ0डी0आई0 दे ही रहे हैं, आज बुलेट ट्रेन का ठेका जापान को दे सकते हैं तो क्या पेड़ लगाने का काम नहीं दे सकते उन लोगों को? जब हम फेल हो गए, हमारे एन0जी0ओ0 फेल हो गए, आज इतने एन0जी0ओज़0 हैं कि आप लिस्ट निकाल लीजिए तो ताज्जुब मान जाएंगे कि कितने एन0जी0ओज़0 इस देश में पेड़ लगा रहे हैं और पर्यावरण ठीक कर रहे हैं। कितना पैसा उनको मिल रहा है और क्या पर्यावरण ठीक हुआ है? दिल्ली के क्लब में शाम को पर्यावरण ठीक करते हैं और टी0वी0 पर बैठ कर हिन्दुस्तान भर को उपदेश देते हैं। मैं कुछ बोल देता हूं तो बुरा लग जाता है। मैं देखता हूं कि कुछ लोग रोज टी0वी0 पर बैठ जाएंगे डिस्कशन के लिए। वहां इतने उपदेश देंगे कि उनसे बड़ा ज्ञाता ही कोई नहीं है। आप लोग भी सुनते होंगे उनके उपदेश। यह टी0वी0 वालों ने नया ट्रेंड चलाया है कि किसी को बिठाना हो, अगर हर्ष वर्धन जी पर हम एक टिप्पणी कर दें तो शाम तक देखें और कल तक तो हमारे ऊपर कितनी टिप्पणियां होंगी कि हमने क्या कहा? हमने तो इतना ही कहा कि पाकिस्तान ने उनको फांसी की सजा दी, क्यों दी फांसी की सजा? हम इंटरनेशनल कोर्ट में लड़ रहे हैं, हम अपने यहां आतंकियों को क्यों पाल रहे हैं? 12 साल में कसाब को सजा मिलेगी, अफज़ल गुरु जिसने पार्लियामेंट पर अटैक किया था, उसको 10 साल बाद सजा मिली। सजा भी एक दिन रात में रोक दी गई। हम तो उन आतंकवादियों को पाल रहे हैं, लज़ीज़ कबाब खिला रहे हैं, बिरयानी खिला रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जेलों में जो

हमारे लोग बंद हैं, जाधव जैसे और भी सैकड़ों लोग बंद हैं, उनकी जब यह हालत हो रही है तो क्या कर रहे हैं? तो अतीत में डर हम लोगों को बैठ गया है कि हम कोई निर्णय लेंगे तो आलोचना हो जाएगी, मीडिया आलोचना करना शुरू कर देगा। हम आलोचना के डर से कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। इस निर्णय की स्थिति ने हमको बहुत खराब स्थिति में पहुंचा दिया है।

मैं एक बात और कह दूं कि यह जो हम पोलिटिकल लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ जांच का नया ट्रेंड शुरू किया है, मैं आज ही हिमाचल प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि पिछली सरकार के छ: महीने के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। हमारे उत्तर प्रदेश में जितने अच्छे काम हुए थे, सब पर जांच बैठ गई। तो अगर हमारा काम सरकार बदलने के तुरन्त बाद जांच बिठाना ही हो गया तो फिर कोई बाबू, आई0ए0एस0 कुछ काम नहीं करेंगे। मंत्री जी जब तक फाइल पर नहीं लिखेंगे, हमारा आपका दम नहीं कि उसको ओवर रूल कर दें।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता) : नरेश जी, आप समाप्त कीजिए आपका टाइम खत्म हो गया है। 12 मिनट हो गये, आपका टाइम 11 मिनट था।

श्री नरेश अग्रवाल : आप तो बड़े दिल वाले हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता) : इसलिए मैं 12 मिनट तक रुका।

(2E/SC पर आगे)

SC-NBR/3.20/2E

श्री नरेश अग्रवाल : माननीय मंत्री जी, यह ठीक है कि हम कोयले से चलने वाले उद्योगों को बंद कर रहे हैं, लेकिन आप उसका विकल्प भी तो बनाइए। यह कहा गया

कि हमने दिल्ली से निकाल दिया, वह सब आपने नहीं निकाला, कोर्ट ने आदेश किया, एनजीटी ने तमाम आदेश कर दिए। पेपर मिल वालों को आपने मना कर दिया, लेकिन अगर alternatively सब इंडस्ट्रीज़ को बंद करते चले गए, तो वह भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी। आज नदियों के प्रदूषण की क्या हालत है? गंगा पर प्रदूषण समाप्त करने के लिए कितना रुपया खर्च हो गया? हम लोग तो गंगा के पास ही रहने वाले हैं - "हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है" - हमारे हरदोई के पड़ोस से तो गंगा निकलकर गयी है, कन्नौज हरदोई का बॉर्डर है। गंगा का प्रदूषण केवल चिताएं जलाने से नहीं है, गंगा का प्रदूषण, आपकी फैक्ट्रियों ने जो कैमिकल डाल दिया है, उसकी वजह से है। वहां मछलियां मर गयीं, कछुए मर गए। यही pollution को खाते थे, गंगा को clean रखते थे, लेकिन हमारे इस pollution ने हमारी उस स्थिति को खराब कर दिया। जिस शहर की नदी गंदी हो, वह शहर सबसे गंदा होता है। आप चलकर यमुना का हाल देख लीजिए। हम जब कभी ट्रेन से आते हैं और यमुना नदी के ऊपर से ट्रेन निकलती है तो वहां बिल्कुल काला पानी है,उसमें से बदबू अलग आती है, पता नहीं कैसे गरीब लोग वहां रहते होंगे! जब इतनी काली हमारी दिल्ली की यमुना है, तो यहां पर प्रदूषण की स्थिति क्या होगी, दिल्ली की क्या हालत होगी? आपने आज निकाला कि हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम को electric system करने जा रहे हैं। आप ऐसा कब कराएंगे? यहां पर Urban Development Minister भी बैठे हुए हैं। मैं कहता हूं कि ठीक है, alternate निकालिए, किसी तरह से pollution दूर हो। दस साल पुरानी गाड़ियों के संबंध में आदेश हुआ था, फिर वह रुक गया। यह सही है कि बहुत पुरानी गाड़ी बहुत अधिक pollution फैलाती है। आप उन गाड़ियों को खत्म ही करिए, ऐसा न हो कि

आपकी दिल्ली की खराब गाड़ियां हमारे उत्तर प्रदेश में पहुंच जाएं, क्योंकि दिल्ली में बैन हुईं और उत्तर प्रदेश में खुली रहीं तो सब गाड़ियां दिल्ली से उत्तर प्रदेश में पहुंच जाएंगी, हरियाणा में पहुंच जाएंगी और वहां pollution फैलाएंगी। आप कोई एक नीति बनाइए, कोई ऐसा विकल्प बनाइए कि हिन्दुस्तान की pollution की स्थिति सुधरे। हमारे यूपी में लखनऊ, गाजियाबाद और नोएडा में तो दिल्ली से ज्यादा pollution है, वहां की स्थिति तो और भी ज्यादा खराब है। तो हर्ष वर्धन जी, हर्ष के साथ, खुशी के साथ आप कोई बड़ा निर्णय लीजिए। आपको उसमें क्या दिक्कत है? आप इतनी बड़ी majority के बाद अगर निर्णय लेकर उसको ठीक न कर पाएं, तो यह ठीक नहीं है। आप तो डॉक्टर रहे हैं, आप तो नब्ज़ पकड़कर जान जाते होंगे कि क्या समस्या है। हम लोग तो राजनैतिक डॉक्टर हैं, हमारे पास जब कोई गांव वाला आता है तो हम दूर से ही जान जाते हैं कि यह किस काम के लिए आ रहा है। उसी तरह से आप भी डॉक्टर हैं। आप पर्यावरण के डॉक्टर बन जाइए और इसको ठीक करिए, ..(समय की घंटी).. यही हमारा आपसे अनुरोध है। हम आलोचना करने नहीं आए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रदूषण ठीक हो और हम सब भी एक अच्छी जिंदगी जी सकें। सर, यूरोप में अगर ढाई एमजी से ऊपर प्रदूषण पहुंच जाए तो हल्ला मच जाएगा, लेकिन हमारे यहां ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको ठीक कीजिए, यही हमारा आपसे अनुरोध है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समाप्त)

DR. T. SUBBARAMI REDDY (ANDHRA PRADESH): Sir, the surge in spread of toxic air in Delhi is giving so much trouble that we are also not able to go for walking. I am afraid to walk and putting up weight because of this

problem. I must say, according to a recently published study in a Journal of the American Medical Association, the risk is even higher among elderly people, females and result in premature death of elderly. So, it is very dangerous.

The most important thing is to have greenery. Even though New Delhi is having good plantation, still it is not sufficient. The amount of air pollution is going up exponentially. So, we need greenery not only within the city limits or surroundings of city, but also in outskirts, such as Dwarka and beyond this. We need massive plantation. So, I would suggest for consideration of the hon. Minister, Dr. Harsh Vardhan, that plantation has to be taken up on a massive scale. What we are planting now has to be multiplied ten times in all places. Another most important thing is, there should be coordination between the Governments of Punjab, Haryana and Uttar Pradesh. I am happy, recently, the Central Government appointed a High Level Committee headed by the Principal Secretary to the hon. Prime Minister.

(CONTD. BY USY/2F)

DR. T. SUBBARAMI REDDY (CONTD.): They are already coordinating between the Chief Secretaries of these three States. It is a good step. But,

at the same time, I would also like to say that the National Green Tribunal is also playing a very important role. It has formulated a graded response action plan for combating the air pollution in Delhi. But, it lacks coordination among many stakeholders. There is a news report that the NGT and the SC-mandated Environment Pollution Control Authority (EPCA) do not see eye to eye. It is a very dangerous situation. They must have a good relationship. But, there is a great confusion. I would like to know who is going to do away this confusion and make them work together.

I am happy to know that the Principal Secretary to the hon. Prime Minister has drafted a Twelve Point Draft Action Plan. I would like to know what this Twelve Point Draft Action Plan is. How is it going to achieve the goal? What is the time limit? How is it going to solve the problem of pollution?

Solid waste management is another major reason of pollution. The Municipal Corporations of Delhi are not properly doing solid waste management. Last week, I had raised this point during the Zero Hour also. But, there is no response till now. Improper and poor solid waste management is causing a lot of pollution.

Vehicular pollution is another major problem in Delhi. Of course, in modern life the cars and transportation are very important. But, the cars are

growing at a rapid pace in the city. It is also very important to see how best we can limit the cars on the roads by providing alternative public transport system. The increasing number of cars may, perhaps, be controlled by providing more and more air-conditioned buses and by encouraging the employees to use the public transport system instead of using their individual cars for commuting. Of course, it is difficult to implement. But, we will have to apply our mind as to how best we can do it.

The pollution in the Ganges and the Yamuna is yet another major cause of concern. I was very happy that the NDA Government was aggressively promising to clean the rivers, particularly the Ganges and the Yamuna. They were trying to get assistance from the World Bank also for this purpose. But we still find – as Shri Naresh Agrawal was telling about the Ganges and Yamuna – that nothing much has improved. So, I would like to know from the Government as to what their action plan in this regard is. How are they going to improve the condition of the Ganges and the Yamuna?

You have also to improve the public transport by integrating the Metro Rail and the Delhi Transport Corporation services through Journey Planner Apps and linking ticketing in DTC buses, the State Transport Cluster Buses

and trains. It is very important. If you improve these facilities, then, people would not use their individual cars, scooters, and motorcycles.

You have also to ensure the completion of the Eastern and the Western Peripheral Expressways within the target dates.

One of the action plans is to encourage electric vehicles, including prioritizing their use for public transport and providing last-minute connectivity. Of course, electrifying cars may take some more time. But, at least, electric buses and other public transport systems may be provided.

In conclusion, I would like to reiterate that the number of increasing vehicles on the roads, lack of green cover, crop residue burning by the farmers in the neighbouring States are the major sources of pollution. Therefore, the Governments of Punjab, Haryana and Uttar Pradesh should frame plans to curb and monitor the stubble burning. The Ministry of Environment must develop a dashboard of all red category pollution units and ensure that all these units have installed certified pollution meters on the premises. I have already emphasized on the need of solid waste management in an effective manner. There should always be focus on hundred per cent solid waste management. The Municipal Corporations of Delhi play a very important role in this regard. Then, a High Level Task Force, headed by the Principal Secretary, had been constituted. I would

again like to call upon him and also the Government as to what the Twelve Point Draft Action Plan is.

(Contd. by 2g – PK)

PK-HMS/2G/3.30

DR. T. SUBBARAMI REDDY (CONTD.): We would like to know, as early as possible, what the 12-Point Action Plan is, how it is going to solve the problem of air pollution and what is the timeframe, etc. With these words, I pray to God that the prestigious city of India, the Capital, New Delhi, becomes pollution free and remains a prestigious city. We all must work together to see that the Delhi city becomes a clean city. Thank you.

(Ends)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you, Dr. Reddy. The next speaker is Dr. Vinay P. Sahasrabuddhe.

डा0 विनय पी0 सहस्त्रबुद्धे (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष जी, दिल्ली के प्रदूषण के विषय पर सदन में चर्चा चल रही है। मैं मानता हूं कि यह बड़ी प्रासंगिक चर्चा है और प्रदूषण का विषय केवल कहने का विषय नहीं है। इस पर लंबा भाषण देना या उपदेश करना तो आसान है, मगर यह हम सब की जिंदगी से जुड़ा एक विषय है, इसलिए मैं मानता हूं कि यह हमारे क्रियान्वयन में भी झलकना चाहिए। Our own life-style also has to be very environment-friendly. If that is not happening, all sermons about

environment and ecological considerations, I am afraid, are going to be sounding very hollow. महोदय, यह एक अल्पकालीन चर्चा है, मगर प्रश्न दीर्घकालीन है। यह कोई विगत तीन-साढ़े तीन सालों में निर्माण हुआ प्रश्न नहीं है और मैं मानता हूं कि केवल सरकार के दरवाजे पर आकर इस बारे में दुहाई दें और समस्या के समाधान की बात करें, यह भी शायद बहुत जिम्मेदाराना व्यवहार नहीं होगा, जितना कि हम सब मिलकर इस विषय में सोचें और क्रियान्वयन के धरातल पर अपने आचरण में कोई बंधन लाएं या कुछ-न-कुछ करें।

महोदय, अच्छी बात यह है कि विगत तीन सालों से आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, जो सरकार केन्द्र में काम कर रही है, उसने पर्यावरण के विषय पर कुल मिलाकर एक व्यापक सोच बनायी है। हमारे प्रधान मंत्री, जब गुजरात के मुख्य मंत्री थे, तब भी उन्होंने पर्यावरण के विषय पर कुछ लेखन किया था और नीतिगत बातें रखी थीं और एक प्रतिबद्धता के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। We are committed to the protection of environment और इसलिए इसी सरकार ने स्वच्छ भारत जैसे कार्यक्रम को हाथ में लिया है, जोकि पर्यावरण के लिए भी है। इस के बाकी सामाजिक और आर्थिक पहलू भी हैं, मगर हम पर्यावरण के पहलू की भी अनदेखी नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि इस सरकार की सोच एक मूलभूत दिशा को इंगित करती है। महोदय, हमारे देश में वर्षों से इस बारे में डिबेट हो रही है। अब कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ecology एक luxury है और यह एक वातावरण बनाया गया था कि either you can protect environment or you can promote industry, मतलब उद्योग को बढ़ावा देना और पर्यावरण की रक्षा में कोई द्वैत है, ऐसा वातावरण बनाने की भी कोशिशें

होती रही हैं। महोदय, हमारी सरकार की यह नीति है कि विकास और पर्यावरण हाथ-में-हाथ डालकर चल सकते हैं। अत: पर्यावरण का भी विकास होना चाहिए और विकास का पर्यावरण भी बरकरार रहना चाहिए। मैं मानता हूं कि इस मूलभूत बिंदु के बारे में हम सभी को मिलकर सोचना चाहिए। तीसरी बात, इस सरकार ने पहली बार इस देश में वातावरणीय परिवर्तन या climate change के बारे में पर्यावरण विभाग में ही एक अलग विभाग का निर्माण किया, जो समय की आवश्यकता के अनुरूप था और अपने उत्तरदायित्व को पहचानते हुए इस सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया।

महोदय, कई बार लोगों को लगता है कि नया और अलग क्या हो रहा है? मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश में सोलर एनर्जी के बारे में काफी समय तक चर्चा चलती रही, मगर सोलर एनर्जी को एक international relations का platform बनाते हुए एक International Solar Alliance के नाम से एक संस्थागत ढांचे के निर्माण के लिए आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी को प्रधान मंत्री बनना पड़ा, इस वास्तविकता को भी हमें समझना पड़ेगा। उपसभाध्यक्ष जी, हम यह भी जानते हैं कि सरकार में आने से एक साल पहले, वायु प्रदूषण की समस्या कोई कल-परसों से चर्चा में नहीं आयी है, यह समस्या पहले से थी।

(2एच/एलपी पर जारी)

LP-PB/3.35/2H

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे (क्रमागत) : मगर इस पर कारगर उपाय ढूंढ़ने के लिए देश में पहली बार - और हम सबको यह समझना चाहिए कि National Air Quality Index इस देश में अप्रैल, 2015 में पहली बार बना था, क्योंकि हम हवा, जल, प्रदूषण के बारे में

चिंतित हैं, अपने दायित्वों को समझते हैं और कारगर योजना और उपाय करने की दिशा में भी काम करना चाहते हैं।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं यह मानता हूं कि इस सरकार ने कुल मिलाकर तीन विषयों पर बहुत गंभीरता से काम किया है। यह अच्छी बात है कि इस सरकार के चलते तीन अच्छे व्यक्तियों को इस मंत्रालय का कार्यभार मिला। हम यह भी जानते हैं कि इससे पहले, जिन्होंने दायित्व संभाला, वे कैसे-कैसे टैक्स लाए और उनकी कैसी-कैसी चर्चा मीडिया में चलती रही। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, मगर एक प्रामाणिकता से, कमिटमेंट के आधार पर, पर्यावरण की रक्षा में भी लोग आर्थिक प्रदूषण करते रहे, उससे पूरा बचते हुए, पूरे कमिटमेंट के साथ, प्रतिबद्धता के साथ इस सरकार में बैठे लोगों ने पर्यावरण की रक्षा का काम किया है। मैं तीन बिदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहला बिंदु अध्ययन करना है। पर्यावरण का विषय ऐसा नहीं है कि मन में बात आई, निष्कर्ष निकाल लिया और आगे बढ़ें। यह नीतिगत सोच का विषय होता है और इस सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर, जैसे सरकार के पृथ्वी विज्ञान विभाग ने, Earth Sciences Department ने Scientific Assessment of Delhi Winter Air Quality Crisis, पर 6 से 16 नवंबर के दरम्यान पूरा अध्ययन करके अपने निष्कर्ष निकाले हैं और यह बार-बार होता जाएगा। अर्थ विज्ञान मंत्रालय या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा इस तरीके का एक प्रयास करना, यह अपने आप में इस दिल्ली शहर के पर्यावरण के संदर्भ में चर्चा के जितने भी सारे बिंदु आते हैं, मैं मानता हूं कि उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। केवल इतना ही नहीं, उसके पहले भी 2017 के जून महीने में ICMR के द्वारा Effect of Air Pollution on Acute

Respiratory System पर एक रिसर्च की गई कि कुल मिलाकर हमारे फेफड़े के स्वास्थ्य की स्थिति क्या बनती है। Indian Council of Medical Research के द्वारा एक रिसर्च की गई। इसके जो निष्कर्ष आए, उन पर यह सरकार silos में काम नहीं करती। इस सरकार में ऐसा कभी नहीं होगा कि बायाँ हाथ क्या करता है, उसका दाएँ हाथ को पता नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, पर्यावरण मंत्रालय है, ये सारे मंत्रालय मिलकर पर्यावरण की त्रासदी का, इस चुनौती का सामना करने के लिए खुद को, लोगों को और अन्यान्य सरकारों को संन्नद्ध कर रहे हैं।

महोदय, मैं नई तकनीक की बात भी कर सकता हूँ। हमारे श्रीमान नितिन गडकरी जी नई-नई प्रतिभाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। यह जो पराली की बात आती है कि हमारे जो पौधे हैं, जब तक हम उन्हें पराली से नहीं निकालते हैं, जिसको जलाया जाता है, उसके लिए कौन-सी नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है? इस पर भी शोध कार्य जारी है। मैं मानता हूं कि किसानों के पास जाकर इसके बारे में भी जन-जागरण होगा। ये जो नये विकल्प सामने आ रहे हैं, मैं मानता हूं कि इसके क्रियान्वयन के धरातल पर भी हम कुछ न कुछ कर पाएंगे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक क्रियान्वयन की बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि Ministry of Environment and Forest के द्वारा एक Apex Committee और Working Group भी बनाया गया है, जिसमें सारे विभाग इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं और इस वर्किंग ग्रुप की बैठकें भी निरंतरता से हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि केवल दिसंबर में क्राइसिस होता है, चर्चा होती है, सुर्खियाँ बनती हैं, विमानों की आवा-जाही में कुछ परिवर्तन होता है कि कुछ क्राइसिस आया है तो चलो, बस उसी के ऊपर चिंता

करो। यह ऐसा विषय नहीं है। इस विषय पर साल भर कुछ न कुछ अध्याय होता रहा है और नीतिगत उपाय, संस्थागत उपाय के माध्यम से इस सरकार की इस समस्या को हल करने की एक प्रणाली है।

महोदय, जहाँ पर GRAP का विषय आया, Graded Response Action Plan for Control of Pollution, यह जो GRAP है, इसके बारे में भी एक संस्थागत ढाँचा बना है और अभी सारे लोग मिलकर इसके क्रियान्वयन की तरफ ध्यान दे रहे हैं। मैं मानता हूं कि यह भी एक महत्वपूर्ण पहल इस सरकार की ओर से हुई है, जिसकी हमें अनदेखी नहीं करनी चाहिए।

महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसका जिक्र पूर्व वक्ताओं ने भी किया कि माननीय प्रधान मंत्री के कार्यालय के अंदर, प्रधान मंत्री के जो सचिव हैं, उनकी अध्यक्षता में एक हाई पावर ग्रुप बना है। यह केवल एक या दूसरे मंत्रालय से संबंधित विषय नहीं है, बल्कि पूरी कैबिनेट का इसके ऊपर ध्यान है, इसलिए स्वयं प्रधान मंत्री के नेतृत्व में, जो प्रधान मंत्री कार्यालय है, उस कार्यालय के द्वारा भी इस विषय की समीक्षा निरंतरता से और समय-समय पर, बार-बार करने की एक कवायद शुरू हुई है।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपको बताना बताना चाहूंगा, यद्यपि हमें इसको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए, बावजूद इसके, दूध का दूध और पानी का पानी साफ होना चाहिए।

महोदय, हम यह मानते हैं कि दिल्ली के प्रदूषण के बारे में, दिल्ली की हवा के प्रदूषण के बारे में दिल्ली सरकार की भी कोई जिम्मेदारी है।

(KLG/2J पर जारी)

KLG-SKC/2J/3.40

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे (क्रमागत): यद्यपि केन्द्र सरकार दिल्ली सरकार के साथ समन्वय बैठाती है। कई बार दिल्ली सरकार ने वायदे किए, आश्वासन दिए, जैसे हेलीकॉप्टर और वाहनों के माध्यम से सड़कों पर पानी फेरा जाएगा, जिसके कारण प्रदूषण को समाप्त करने की या कम से कम उसको काबू करने की कवायद की जाएगी, मगर जहां तक मेरी जानकारी है, उस विषय में कुछ हुआ नहीं। किसी को तो दिल्ली सरकार को भी यह कहना चाहिए। यहां पर दिल्ली सरकार के काफी मित्र हैं, जैसा कि ध्यान में आ रहा है, वे भी जरूर बताएं। They can use their good offices to impress upon the minds of the leaders of Delhi Government that they also have to contribute and they also have to shoulder the responsibility.

महोदय, इसके पहले कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं, मैं तीन-चार सुझाव देना चाहता हूँ। पहली बात यह है, जैसा कई बार जिक्र आता है हरियाणा, उत्तर प्रदेश का, जिसका अभी नरेश जी ने भी जिक्र किया, जो किसानों के द्वारा खेतों को जलाए जाने की प्रक्रिया होती है, उसके कारण प्रदूषण होता है। मैं जानता नहीं कि इसमें कितना तथ्य है? हां, यह 25 परसेंट, 30 परसेंट होता है या 40 परसेंट होता है, जो भी हो, कुछ मात्रा में तो यह होता ही है। मेरा मानना है कि हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, यहां दिल्ली में भी किसानों के अपने संगठन हैं, अच्छे-खासे फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको भी एक बार कभी इकट्ठा बुलाया जाए और उनके साथ मंत्रणा की जाए। अगर किसानों के अंदर भी दिल्ली की समस्या को लेकर जागरूकता का निर्माण करते हैं, तो मैं आश्वस्त हूँ कि दिल्ली की समस्या के लिए ये जो आजू-बाजू के

किसान हैं, निश्चित रूप से वे सहयोग करने की मुद्रा में आएंगे। दिल्ली में जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, RWAs हैं, दिल्ली की सरकार का यह दायित्व बनता था कि उनको भी इकट्ठा करती और उनके साथ भी समन्वय करती, उनको भी बताती, यह छोटा-मोटा प्रदूषण होता है, जैसे हम देखते हैं कि जाड़े के मौसम में हम जो हीटर चलाते हैं, उससे भी प्रदूषण बनता है। तो इन सारे विषयों के बारे में भी कुछ न कुछ करने की आवश्यकता है। दिल्ली में लाखों ट्रक्स आते हैं, उनके जो ड्राइवर्स हैं, उनके भी संगठन हैं, ट्रक मालिकों के संगठन हैं। उनके साथ भी समन्वय बैठाते हुए, संपर्क सेतु निर्माण करते हुए बात होनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि इस विषय में भी निश्चित रूप में कुछ करने की आवश्यकता है।

एक जो दूसरा बिन्दु है, वह नेशनल ग्रीन ट्रिबुनल के बारे में है। कई बार, उपसभाध्यक्ष जी, समझ में नहीं आता कि नेशनल ग्रीन ट्रिबुनल क्रियान्वयन के लिए ऐसे अक्षम, actions which are non-implementable, ऐसे डिसीज़ंस क्यों देते हैं? अगर ऐसे डिसीज़ंस देते हैं, तो एग्जीक्यूटिव के क्षेत्र में एक दृष्टि से अतिक्रमण करते हैं। इसके बारे में भी हमें मिल-बैठ कर कुछ सोचना चाहिए। नेशनल ग्रीन ट्रिबुनल, ऐसा नहीं है कि वह जो चाहेंगे, वह अमल में आएगा। वह निर्देश तो दे देंगे, मगर जो निर्देश अमल में नहीं आ सकता है, ऐसे निर्देश का उपयोग क्या है? इसलिए मैं मानता हूँ कि इस विषय से संबंधित जो संस्थाएं हैं, सरकारें हैं, उन्हें मिल-बैठ कर इस चुनौती का सामना करने के लिए एक एक्शन-प्लान अगर हम बनाते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पर्यावरण के विषय में एक अत्यंत सजग सरकार के होते हुए इस विषय पर काबू पाना

इस चुनौती को मात करना, यह हमारे लिए बिल्कुल कठिन नहीं है। मैं मानता हूँ कि निश्चित रूप से हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे।

(समाप्त)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you. The next speaker is Shri A. Navaneethakrishnan; you have got seven minutes.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (TAMIL NADU): Sir, air pollution in Delhi has now become unmanageable; it has gone out of control. People in Delhi are living in fear. Delhi has become a gas chamber. It is no longer a good place of habitation for human beings. What is the solution? Time and again, the hon. Supreme Court and the National Green Tribunal have been passing orders. Are they sufficient for our citizens? I hope and trust that my friend, Shri Derek O'Brien, has got statistics about deaths caused by air pollution. I hope he has got a reliable data with him. The constitutional right to life free from pollution has not been guaranteed by our administration though the same has been guaranteed in our Constitution. Permit me to read Article 48A of the Constitution – 'protection and improvement of environment and safeguarding of forests and wildlife'.

(CONTD. BY HK/2K)

HK/2K/3.45

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (CONTD.): "The State shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wild life of the country." I want to repeat the words "The State shall endeavour to protect and improve the environment..." Though it is given under chapter "Directive Principles of State Policy", thanks to our Supreme Court judgement, it is an enforceable right. If our environmental rights are violated, we can move the Supreme Court, we can move the NGT or we can move the High Court and get it enforced. So, thanks for the intervention made by hon. Supreme Court. What are the causes of this air pollution? The major sources are fuel wood and biomass burning, fuel adulteration, vehicular emission and traffic congestion, large-scale grass residual burning in agricultural fields in autumn and winter months. These are the major sources of smog, smoke and air pollution. Also, 2016 Environment Performance Index ranked India 141 out of 180 countries. Now, the constitutional right is enforceable. Our Government is taking all steps to prevent air pollution. Now, the latest scheme is 12-Point Draft Plan which is formulated to combat air pollution in Delhi. It is also in place. But there is no guarantee that Delhi will be free from air pollution because every year we are purchasing more number of cars, we are roaming in individual vehicles,

we are driving and travelling in individual cars and are not using public transport system. Fortunately, our hon. Prime Minister while inaugurating the Metro requested and advised the people to make use of public transport system. How far it will be accepted and followed is not known. The Constitution contemplates an enforceable constitutional right with regard to environment. Our Government is taking steps but Delhi is becoming a gas chamber. So, what is to be done? My suggestion is that we must have self-restraint. We should not use our own vehicles; we must make use of public transport. We cannot control the agriculturists of Punjab, Haryana and Rajasthan not to resort to grass residuals burning or stubble burning because they have got their own problems. So, unnecessarily, they don't do it. I think they are justified in doing it. Unless alternative method is available to them, why should they not resort to this? So, for their means of livelihood, they have to do it. To save Delhi, subject to correction and approval by this House, the Session may be shifted to southern part of our nation so that our northern friends can come to South India and enjoy food and climate which is free from pollution. So, I welcome all the northern friends to South India and have a good, peaceful and effective Session. We can hold the Session in a place which is most compliant to environment. There is nothing wrong in it. …(Interruptions)… Once our leader, Puratchi

Thalaivar M.G. Ramachandran, vehemently argued for shifting our Supreme Court of India to Nagpur or any other central place of India. His point was that poor people cannot be made to travel such a long distance to Delhi and it was rebutted by Mr. Ram Jethmalani. I attended that meeting. That is only for the sake of convenience that I am making this point.

(Contd. by KSK/2L)

KSK/SCH/3.50/2L

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (CONTD.): Delhi is not good for inhabitation. Definitely, it cannot be. Everybody is making use of it, polluting it and going back to their native places. So, my humble submission is that any one of the Sessions may be held in Nagpur, Bengaluru, Chennai, Hyderabad, Mumbai, or anywhere else. It is also very useful for national integration. I hope that our Central Government is doing all the work, or, taking all the steps to prevent the air pollution, but changing the venue of Session may also be considered as one of the plans to prevent air pollution in Delhi. Thank you, Sir.

(Ends)

SHRI DEREK O'BRIEN (WEST BENGAL): Sir, I hope you will not look at the time today because this is my maiden speech. It is my maiden speech in my new term.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): You have six minutes.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, before I begin, I must thank and acknowledge my Party, the Trinamool Congress, and its leader, Mamata Di, to repose the faith to have me elected again and have me back in this House for another term.

Sir, this issue today is very important. There is no doubt about it. Last week, we had a Short Duration Discussion listed on sports. My appeal to the hon. Chairman, through you, Sir, is that next week, we only have one Short Duration Discussion left, and as important as this issue is, of pollution in Delhi, we need to get an issue like farmer distress listed for a Short Duration Discussion in Rajya Sabha. Sports is important. Pollution is important. Jobs are important. The economy is in a mess. That is important. There are so many issues, but one of these other three issues must be taken up. A lot of parties have given notices and this is my humble appeal to the hon. Chairman to take up one of these issues - the jobs, the economy or the farmer distress.

Sir, I have four or five broad numbers just to illustrate the point. Then, I want to talk a little about the causes for pollution and try and get a better understanding about it. Then, I will make two or three suggestions on policy

intervention. And, finally, I want to conclude by offering three or four best practices which are being practised by some other States, and maybe the Minister would consider that.

Sir, the first on the broad issues is this, the numbers are very scary, and this is not about this Government or the last Government; this is an ongoing problem for many decades. The population of Ireland or the population of Palestine is equivalent to the people who die of indoor air pollution in the world. Sir, there are basically two broad aspects to pollution, and we have to address both these aspects. One is the indoor air pollution and the other is the outdoor air pollution. To give you these numbers, the outdoor air pollution, in fact, affects less people in the world. About 37 lakh people die of outdoor air pollution. The indoor air pollution is also a huge killer. The second figure, which is alarming, is if you look at the 2013 World Bank Report, and if you look at environmental degradation, they say that 5.7 per cent of GDP is lost because of this poor environmental degradation. Sir, I think that number - 5.7 per cent of GDP - would mean total health contribution and the total education contribution, which would still be under 6 per cent of GDP. That is the second scary number. Sir, out of 37 lakh people in the world, who have premature deaths because of COPD and asthma, 25 lakh are Indian. One of the speakers mentioned

about the quality of the index. One in two Indians lives in areas that exceed that index, which we call the Indian National Ambient Air Quality Standards. So, these are very scary numbers.

I wish to go into the causes, highlight some of the causes so that we can look for some solutions. The first thing which I want to table in this House is that there are two major causes for indoor pollution. So, the point we am making here is that indoor pollution is a bigger killer than outdoor pollution, and in all the studies which have been done, either through NGOs or through IIT, Kanpur, and other groups, there are two killers for indoor pollution. The first big killer is, believe it or not, the mosquito coil. So, where there are mosquitoes -- obviously, in the poorer areas, you burn more mosquito coils -- COPD cases go up, asthma cases go up.

(Contd. by 2M – GSP)

GSP-RPM/3.55/2M

SHRI DEREK O'BRIEN (CONTD.): So, mosquito is linked to the coil and that is linked to Asthma, the COPD. This is the first one. The second one, which I know is often used for good reasons for religious purposes and we all use it in Hinduism, Christianity or Sikhism is, what we call in Bangla, the *dhoop*, the *Agarbatti*. That also is a big killer as far as indoor pollution is

concerned. So, we need to address these two big issues on indoor pollution.

SHRI JAIRAM RAMESH: *Chulhas* are also a reason.

SHRI DEREK O'BRIEN: Yes, *chulhas*. Let me come now to the issue of outdoor pollution. Sir, there are four causes and we need to address all four. Sir, twelve hundred cars are registered in Delhi every day. If you take 1,200 cars, you can fill the Eden Gardens in Kolkata. So, the first cause is more private transport, as many have suggested. Sir, the second obvious cause for outdoor pollution -- and, which I think, the Member from the BJP addressed in his opening remarks, you need to look that way too -- is the over-dependence on coal, and, the faster we move away from that, the better. The third one, Sir, is industrialization and we need to be very, very strict with imposing these rules, whether it is for industrial clusters, whether it is for restaurants, whether it is for thermal power plants. So, these are the issues.

Sir, regarding policy intervention, very quickly, I want to speak about it in three parts. Sir, we need to look at all forms of pollution and not restrict ourselves to one form of pollution. Second, why only Delhi, we need to look at the other metropolitan cities and we also need to look at the smaller towns. For policy intervention, Sir, we need to develop an Air Quality

Information System. So, these are policy interventions which will have long-term solutions.

Sir, for good practice, I want to give you three or four examples. Let me give two from my State. Three years ago, we started a scheme, Sabujshree, which simply means that because we need more greenery, every time, a girl child is born in Bengal, a sapling is planted. Now, you will say, why do you discriminate against the boys. It is not that; we hope to include the boys also. So, fifteen lakh saplings are planted every year because it is linked to the birth of a girl child. So, that is one way to increase the greenery.

Sir, the second example from my State is the Green University Bill, which was passed in the Assembly in October-November, 2017, and, the West Bengal Green University has been set up to be a centre for excellence, a centre for learning so that more research can be done in these fields. These are the two examples from the State of Bengal. Sir, I can give you one example from Delhi. Over the last one year, the plantation has increased by about one per cent, maybe 0.9 per cent, because of more efforts towards greenery. During Diwali also, there was also the 'Say No To Crackers' campaign.

Sir, I want to end by sharing with you a statistic which, I think, will make all of us really stand up and take notice, and, this is not from some little village hospital. This is from the All India Institute of Medical Sciences. Please have a look at these figures. In 2005, the number of patients who were admitted into the Respiratory Ward was 5,020. I do not have the figures for 2017 but this figure rose from 5,020 in the year 2005 to 37,000 in the year 2015.

Sir, I would conclude by appealing to you, as I earlier said, to take up another Short-Duration Discussion next week, and, in all humility, also by appealing to the BJP Government that in their efforts to choke the Chief Minister of Delhi -- allow him to do his work rather than try and choke him -- do not end up choking the children of Delhi. Thank you, Sir.

(Ends)

(Followed by SK/2N)